

शहर में प्रशासन की लापरवाही का नजारा...



राजधानी भोपाल में इन दिनों कई क्षेत्रों में सीवेज के नाले इस तरह खुले छोड़ दिये गये हैं जो घटना-दुर्घटना व गंदगी का कारण बन रहे हैं।

इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिये **अच्छी खबर**

उम्मीद छोड़ चुके लोगों को आयुर्वेद अस्पताल में अब मिल रही खुशियां

भोपाल, दोपहर मेट्रो

संतानहीनता या बांझपन (इनफर्टिलिटी) की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिये नयी खबर है और इसका इलाज आयुर्वेद में नजर आ रहा है जबकि आमतौर पर एलोपैथिक इलाज ही पसंद करते हैं। दरसअल राजधानी में पं. खुशीलाल आयुर्वेदिक विज्ञान केंद्र में आयुर्वेदिक दवाओं और खान-पान में बदलाव के जरिये न सिर्फ बांझपन का इलाज हो रहा है, बल्कि गर्भधारण से लेकर सुरक्षित प्रसव तक कराया जा रहा है। बताया जाता है कि बीते साल यानि जनवरी 24 से हालिया अप्रैल तक यहां 58 महिलाओं ने यहां बांझपन का इलाज कराया है। इनमें से 30 महिलाएं गर्भवती हुई हैं और 16 महिलाएं स्वस्थ शिशु को जन्म भी दे चुकी हैं। इस बारे में शोध मध्यप्रदेश कार्डिसल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फंड किया गया है, जिसके तहत मरीजों को दो महीने तक मुफ्त इलाज और दवाएं दी जाती हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य



संगठन कहता है कि हर 6 में से 1 दंपती किसी न किसी रूप में बांझपन से जूझता है। यदि 12 महीने तक नियमित संबंध के बावजूद गर्भधारण नहीं होता, तो इसे इनफर्टिलिटी माना जाता है। धूम्रपान, शराब, प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल इनफर्टिलिटी की समस्या को बढ़ाते हैं।

बताया जाता है कि आयुर्वेद में इलाज की कई विधियां हैं जो मरीज के मुताबिक तय होती हैं। खुशीलाल अस्पताल की गायनकोलॉजिस्ट डॉ. मौसमी कुल्हारे का कहना है कि आयुर्वेद में हर मरीज के अनुसार ही इलाज किया जाता है। कई बार ट्यूब ब्लॉकेज, थायराइड असंतुलन,

पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं सामने आती हैं। तनाव और खराब जीवनशैली भी प्रमुख कारण हैं। इलाज का असर यह है कि हाल में करीब दस वर्षों से मां बनने की कोशिश कर रही एक महिला अब सात महीने की गर्भवती है। आईवीएफ में समस्याओं का सामना करने के बाद उन्होंने दो माह आयुर्वेदिक इलाज अपनाया था।

जानकारी के मुताबिक आयुर्वेदिक पद्धति में पति-पत्नी की जांच और कार्डसिलिंग के अलावा योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या भी शामिल है। इसमें जंक फूड, मैदा से परहेज तथा मौसमी फल, मोटा अनाज और औषधियों का सेवन जरूरी माना जाता है।

डाक्टरों का कहना है कि शतावरी और अश्वगंधा जैसी जड़ी-बूटियां प्रजनन क्षमता में सुधार कर सकती हैं। हालांकि, इनकी प्रभावशीलता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। इसलिए, आयुर्वेदिक उपचार अपनाने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है।

जनप्रतिनिधि नाराज, अफसरों ने मनाया पर भूख हड़ताल पर बैठे

भोपाल दोपहर मेट्रो

राजधानी में अधूरी नल-जल योजनाओं को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट, सदस्य विनय मेहर, चंद्रेश राजपूत, देवकुवर हाड़ा समेत सुरेश राजपूत, अनिल हाड़ा और विनोद राजोरिया जिला पंचायत परिसर में कल भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे अफसरों में हड़कंप रहा। जाट ने चार दिन पहले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को इसकी जानकारी दे दी थी। हार्कि आखिरी समय तक कोई हल नहीं निकलने और इन जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन से जिम्मेदार अफसरों की सांसें फूल गईं। इससे पहले बीती रात वे जनप्रतिनिधियों को मनाने में जुटे रहे।

दरअसल, अधूरी योजनाओं के कारण गांवों की बड़ी आबादी गर्मी में पानी के लिए परेशान हो रही है। इसे लेकर जिला पंचायत की बैठक में मुद्दा भी उठ चुका है, पर पीएचई विभाग के जिम्मेदार नहीं जागे। इस कारण जिला पंचायत जाट ने कलेक्टर को पत्र लिखा कि 27 मार्च को साधारण सभा की बैठक हुई थी। इसमें जल जीवन मिशन योजना के तहत विभागीय अधिकारियों को 15 दिन में अधूरी नल-जल योजनाओं को पूरा करने को कहा गया था, लेकिन 23 अप्रैल का दिन भी बीत गया। बावजूद अब तक न तो कोई रिपोर्ट दी गई और न ही गांवों में पेयजल संकट खत्म हुआ है।



निरंकारियों ने मानव एकता दिवस पर किया रक्तदान

शिविर के शुभारंभ के पहले सत्संग भी हुआ

हिरदाराम नगर, दोपहर मेट्रो

संत निरंकारी चेरीटेबल फाउण्डेशन द्वारा 24 अप्रैल, गुरुवार को संत निरंकारी सत्संग भवन, जहांगीरबाद में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 254 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। यह शिविर हमीदिया रक्तदान यूनिट के सहयोग से आयोजित किया गया था। रक्तदान शिविर से पहले संत निरंकारी सत्संग भवन में बैरागढ़ ब्रांच के संयोजक महात्मा महेश वीधानी की उपस्थिति में विशेष सत्संग भी हुआ। 'मानव एकता दिवस' हर साल 24 अप्रैल को निरंकारी मिशन द्वारा बाबा गुरुबचन सिंहजी की स्मृति में आध्यात्मिक भावों के साथ मनाया जाता है। निरंकारी मिशन द्वारा देश भर में रक्तदान की एक प्रेरणादायक श्रृंखला शुरू होती है, जो निस्वार्थ सेवा की सामूहिक भावना का प्रतीक बनकर पूरे वर्ष समाज में प्रवाहित होती रहती है। शिविर की व्यवस्थाएं क्षेत्रीय संचालक महात्मा अखिलेश यादव के मार्गदर्शन में सेवा दल के भाई-बहनों द्वारा सुनिश्चित की गई।



संत कॉलेज में बीसीए इंटरनशिप का समापन

संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में गुरुवार को बीसीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए इन्फोबिब इंफोटेक टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित दो माह के इंटरनशिप कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें 90 छात्राओं ने भाग लिया। इंटरनशिप के दौरान, विशेषज्ञ प्रशिक्षकों आदित्य सिंह चौहान और शुभम श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में छात्राओं ने फुल स्टैक डेवलपमेंट के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया और उनकी तकनीकी दक्षता तथा आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कॉलेज की प्राचार्या डॉ. डालिमा पारवानी कहा कि इंटरनशिप में छात्राओं को तकनीकी की तेजी से बदलती दुनिया में अपने कौशल को लगातार विकसित करने का मौका मिला है। इन्फोबिब इंफोटेक टेक्नोलॉजी के सीईओ गौरव नेमा ने कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई।

दो दिवसीय राष्ट्रीय मिड टर्म सीएमई

आत्महत्या पर मनोचिकित्सकों का दो दिनी सम्मेलन 26 से

भोपाल। इस वर्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकाइस्ट्रिक के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हो रहा है। उक्त जानकारी देते हुए आयोजन समिति के चेयरमैन और मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. आरएन साहू ने बताया कि नेशनल मिड टर्म प्रोग्राम के अंतर्गत समाज और देश की ज्वलंत एवं सामयिक समस्या बन चुकी आत्महत्या प्रवृत्ति को लेकर देश के जाने माने मनो चिकित्सक अपने विचार व्यक्त करेंगे। नेशनल मिड टर्म सीएमई में देश के जाने-माने मनोरोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही विदेश से भी मानसिक रोग विशेषज्ञ भी इसमें सम्मिलित होंगे। साहू के अनुसार आजकल आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है, जो सभी उम्र के लोगों में पाई जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि 14 से 24 साल के युवाओं में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है और मौत का तीसरा कारण बन गई है। इस समस्या की रोकथाम एवं इसके कारण को जानने और भविष्य के लिए ऐसा कार्यक्रम बनना चाहिए, जिससे हम बच्चों को इस आत्मघाती कदम से बचा सकें। साथ ही समाज को और स्वस्थ बना सके। यह एक बहुत ही सामायिक और ज्वलंत विषय है। जिसके लिए हमें सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। जैसा कि सब जानते हैं कि पूरे विश्व में 72 000 लोग हर साल सुसाइड करते हैं। हर दसवें सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। 15 से 29 साल की उम्र में मौत का यह नंबर तीसरा कारण बन गया है। यह भी बताना उचित होगा कि 73 बर सुसाइड उन देशों के लोग करते हैं जो कि लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के देश हैं।

मेट्रो निर्माण से परेशान लोगों की सुध बारिश पूर्व काम पूरा करने के निर्देश

टेकेदारों को समझाइश, 15 जून से पहले करें ड्रेनेज का काम



भोपाल, दोपहर मेट्रो

राजधानी में मेट्रो के काम पहले ही तय समय से काफी पीछे चल रहे हैं। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी भी भोगनी पड़ रही है। ऐसे में अब मेट्रो का काम करने वाले सभी कांटेक्टर को अब बारिश के पहले यानी 15 जून के पहले रोड और ड्रेनेज के काम पहले पूरा करने के लिये कहा गया है। इस संबंध में मेट्रो के एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने सभी कांटेक्टरों को निर्देश दिए। उन्होंने यह निर्देश सुभाष नगर मेट्रो डिपो के निरीक्षण के दौरान दिए हैं। एमडी ने कहा कि जल्दी करें, लेकिन काम की क्वालिटी भी खराब नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेट्रो कार्यालय में सभी कांटेक्टर पैकेज की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद शाम 5 बजे

सुभाष नगर स्थित भोपाल मेट्रो डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो डिपो एंट्री गेट, रैप एवं अनलॉडिंग-बे के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। ट्रेनिंग बिल्डिंग के कार्य एवं डिपो बाउंड्री वॉल को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सब-स्टेशन, ट्रेक, इन्स्पेक्शन-बे, स्टेबलिंग-बे, रिपेयर-बे के काम को भी देखा। इस दौरान मेट्रो के सभी अधिकारियों के साथ साथ कांटेक्टर भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मेट्रो के काम के चलते सड़कों पर बारिश के दिनों में ज्यादा अवरोध कीचड़ और अन्य समस्या बन जाती है जिससे दुर्घटना ट्रेफिक जाम के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। गत वर्ष भी लोगों ने इन समस्याओं का सामना किया था।

मेट्रो एंकर डिफेंस सर्विसेज एवं तैयारी पर प्रेरक सत्र

ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करना आवश्यक जो देशभक्त और आत्मनिर्भर हो

हिरदाराम नगर, दोपहर मेट्रो

बचपन से ही देश सेवा का भाव जागृत किया जाना चाहिए। देश के प्रति दायित्व निर्वहन एक संस्कार के रूप में रोपित किया जाना चाहिए। यह विचार संत सिद्धभाऊजी ने व्यक्त किए। वे नवनिध और मिट्टी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए डिफेंस सर्विसेज एवं उसकी तैयारी विषय पर एक विशेष प्रेरणा सत्र में बोल रहे थे।

कार्यक्रम में सेवा निवृत्त कर्नल नारायण परवानी ने छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में करियर के विकल्प, एनडीए, सीडीएस और एएफसीएटी जैसी परीक्षाओं, चयन प्रक्रिया और आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक मानदंडों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुणों पर जोर दिया और प्रेरक वीडियो दिखाए। कर्नल परवानी ने कहा कि



डिफेंस सर्विसेज सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि मातृभूमि की सेवा का

एक पवित्र अवसर है और ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करना आवश्यक है जो देशभक्त और आत्मनिर्भर हो।

कार्यक्रम में सचिव घनश्याम बूलचंदानी, अकादमिक डायरेक्टर गोपाल गिरधानी और प्राचार्य अमृता मोटवानी सहित शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। संचालन शिक्षिका शशि नाथ ने किया। मिट्टी गोविंदराम पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अजय बहादुर सिंह ने आभार व्यक्त किया।

स्वास्थ्य व पर्यावरण जागरूकता पखवाड़ा

हिरदाराम नगर। नवनिध स्कूल में विश्व स्वास्थ्य दिवस और पृथ्वी दिवस पर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े में छात्राओं ने पेपर प्लेट कला, सजावट, मार्क बनाना और स्लोगन लेखन गतिविधियों में हिस्सा लिया। रनवे पर स्वाद-पोषण की ओर एक कदम में पोषण के महत्व को दर्शाया। छात्राओं ने प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पर पोस्टर बनाए और वेब पेज डिजाइन कर पर्यावरण विषयों को डिजिटल रूप दिया। सीनियर स्टूडेंट्स ने कपड़े व जूट की थैलियों को सजाकर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का संदेश दिया। प्राचार्या अमृता मोटवानी ने अपने विचार रखे।

कई बार न्यायालयीन लड़ाई भी हारनी पड़ रही, करोड़ों खर्च के बावजूद यह स्थिति

50 फीसद जिला रिकार्ड रूम की हालत खराब, खोजे नहीं मिल रहे सरकारी रिकार्ड

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

प्रदेश के जिला रिकार्ड रूम यानी अभिलेखागारों की हालत ठीक नहीं है। इनमें रखे आम लोगों के रिकार्ड में घूना लग रही है, चूहे रिकार्ड बर्बाद कर रहे हैं। यहां तक कि रिकार्ड व्यवस्थित नहीं होने के कारण कई बार आम लोगों को कोर्ट में लड़ाईयां हारनी पड़ रही है। यह हाल तब है जब इन रिकार्ड रूमों को व्यवस्थित बनाने के नाम पर करोड़ों खर्च हो चुके हैं। केंद्र व राज्य दोनों ने यह राशि खर्च दी थी ताकि रिकार्ड रूम को आधुनिक दर्जे का मनेटन किया जा सके, लेकिन कुछ को छोड़कर ज्यादातर जिलों में यह नहीं हुआ।

क्या होते हैं रिकार्ड रूम : आम तौर पर ये जिला मुख्यालय पर होते हैं। इन्हें अभिलेखागार भी कहा जाता है। इनमें पुराने से पुराना रिकार्ड होता है। इनमें भू-अभिलेख से जुड़े रिकार्ड होते हैं। अर्थात् जिले भर की सरकारी निजी जमीन, उनका आवंटन, रकबा, खसरा, उनमें समय-समय पर किए जाने वाले बदलाव से जुड़े सभी दस्तावेज होते हैं।



जबलपुर के रिकार्ड रूम की खासियत

- » दस्तावेज पहले कपड़े के बस्तों में रखे जा रहे थे, अब प्लास्टिक के बॉक्स में है।
- » हर प्लास्टिक बॉक्स की तहसील के हिसाब से कलर कोडिंग की है। उन पर मौजावार, वर्षवार, मदवार केस का विवरण दिया है।
- » प्रत्येक रैक को एक यूनिट नंबर दिया है, प्रत्येक केस का विवरण एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार कर उसमें डाली गई है, जो सर्च करने पर आसानी से सामने आ जाती है।
- » अब आवेदक घर बैठे देख सकते हैं कि उनके काम के दस्तावेज अभिलेखागार में कहां और किस स्थान पर रखे हुए हैं।
- » रिकार्ड रूम के बाद भी कियोस्क लगा दिए हैं, जिन पर खसरा, रकबा व नाम जैसी एंट्रियां डालकर पूरे दस्तावेज निकाले जा सकते हैं।
- » यही नहीं, ये दस्तावेज कहां हैं, इस जानकारी का प्रिंट निकालने की सुविधा भी दे दी है, ताकि प्रिंट उपलब्ध करारक कर्मचारियों से आसानी से समग्र दस्तावेज लिए जा सकें।
- » नवाचार से रिकार्ड रूम व उनमें रखे गए दस्तावेजों की उम्र 50 साल तक बढ़ी।
- » रिकार्ड सुरक्षित हो गया है, अब कोई छेड़छाड़ या गायब नहीं कर सकते।
- » मांगे जाने पर किसी तरह का बाहना नहीं कर सकते, क्योंकि रिकार्ड यह पता रिकार्ड मांगने वाले स्वयं भी लगा सकते हैं।

जबलपुर के रिकार्ड रूम की देशभर में हो रही चर्चा

इन दिनों जबलपुर के रिकार्ड रूम की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी इसमें से बदबू आती थी, रिकार्ड खोजना तो दूर, इसके अंदर प्रवेश करने की हिम्मत तक नहीं होती थी। किसी भी फाइल को हाथ लगाना खतरा से खाली नहीं था। यहां फाइलें बोरियों और गड़ों में रखी जाती थी अब वह एयर कंडिशनर हो गया है। फाइलों पर कोडिंग हो चुकी है। दस्तावेज ऐसे व्यवस्थित रखे हैं, जैसे किसी दवा दुकान में दवाईयों को पूरी जानकारी के साथ क्रमवार रखा गया है। अब जबलपुर के भेड़घाट क्षेत्र के जमीनी दस्तावेज की लोकेशन सिंगल क्लिक में पता चल रही है। ऐसे ही पूरे जिले के वर्षों पुराने दस्तावेजों तक लोगों की पहुंच आसान हो गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि रिकार्ड प्रबंधन के काम में 300 कर्मचारियों की मदद ली। ये चार महीने जुटे रहे। अब क्रमबद्ध आधार पर प्रत्येक दस्तावेजों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। शत-प्रतिशत रिकार्ड अभिलेखागार में उपलब्ध है। नए कर्मचारी भी लोगों की मांग पर आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। आम लोग भी अबलोकन कर सकते हैं। एक तरह से प्रशासन ने रिकार्ड देखने की चाबी आम लोगों के हाथ में दे दी है।

मप्र सरकार हुई सख्त, 1 मई से नया नियम

नरवाई क्यो जलाई... अब नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मप्र सरकार भी अब नरवाई जलाने वाले किसानों पर सख्त है। यह किसान एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर फसल नहीं बेच पाएंगे। ऐसे किसानों को मप्र सरकार की ओर से सालाना मिलने वाले सीएम किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपए भी नहीं मिलेंगे सीएम मोहन यादव ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया। यह फैसला एक मई से लागू होगा।



सीएम यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में बढ़ोतरी होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और जमीन की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके लिए राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। पर्यावरण, मृदा संरक्षण और जमीन की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार अब यह निर्णय ले रही है, जो एक मई से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी

जमीनों, कुएं-बावड़ी, तालाबों और गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से विशेष अभियान चलाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी जल संग्रहण स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्व अधिकारी अपनी भूमिका अदा करें।

सीएम ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी अमृत सरोवर, तालाब, बांध, नहर एवं अन्य जल संरचनाओं को राजस्व रिकार्ड में जरूर दर्ज किया जाए और अभियान में नहर, कुएं और बावड़ी जैसी जल संरचनाओं को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

कॉलेजों में दो शिफ्ट में होगी पढ़ाई, सेमेस्टर सिस्टम भी जारी रहेगा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

कॉलेजों में दो शिफ्ट में पढ़ाई होगी। सेमेस्टर सिस्टम भी लागू रहेगा। साल में एक बार विद्यार्थियों का संवाद वरिष्ठ वैज्ञानिकों से कराया जाएगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में गुरुवार को इसके निर्देश अफसरों को दिए। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बताया कि हम विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति को उनके क्रेडिट स्कोर से जोड़ रहे हैं।

राज्य के स्तर पर हो ग्रेडिंग: प्रदेश के सभी महाविद्यालयों की स्टेट लेवल पर ग्रेडिंग कराई जाए और तीन श्रेणियों में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य एवं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में पुरस्कृत करने की परम्परा शुरू कराई जाएगी। विभागीय अधिकारियों को भारतीय ज्ञान परम्पराओं पर आधारित रोजगारपरक शिक्षा दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि महाविद्यालयों में शोध केंद्र स्थापित कर शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया

जाएगा। प्रदेश के सभी ऐसे क्षेत्रों में, जहां नए महाविद्यालय खोलने की अत्यंत आवश्यकता है, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, अधिकाधिक महाविद्यालय खोले जाएंगे।

एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी: सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश के अधिकाधिक महाविद्यालयों में बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम संचालित किए जाएं। अब तक चयनित हुए सभी महाविद्यालयों में इसी सत्र से बीएससी (कृषि) पाठ्यक्रम की पढ़ाई प्रारंभ करें। प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस संचालित हैं, इनमें से 37 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों में 7 प्रकार के रोजगार आधारित डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालयों में मप्र लोक सेवा आयोग से प्राध्यापकों की भर्ती कराए।

सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी के खिलाफ मंत्री तक पहुंची शिकायत, कई गंभीर आरोप

फिर सुर्खियों में डीईओ कार्यालय



भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राजधानी भोपाल जिला जिला शिक्षा अधिकारी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार मामला डीईओ कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी का है। जिसके खिलाफ अभद्र व्यवहार, पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण, नियमों के विपरीत दो-दो शासकीय भवन लेने, आय से अधिक संपत्ति, शासन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने सहित कई गंभीर आरोपों की शिकायतें स्कूल शिक्षा मंत्री कार्यालय तक पहुंची हैं। जिसके बाद मामले में जिसके बाद मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक संचालक, लोक शिक्षण सभाग भोपाल को जांच के निर्देश जारी किए हैं। यह है पूरा मामला : दरअसल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी सीजे

जॉयसन को लेकर फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भोपाल चैटर नामक संस्था के पत्र पर यह शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री कार्यालय को की गई है। इन शिकायतों में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि जॉयसन को टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। जबकि उन्हें टायपिंग का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। पत्र में टायपिंग परीक्षा, कर्मचारियों के साथ लगातार अभद्र व्यवहार, पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण, नियमों के विपरीत दो-दो शासकीय भवन लेने, आय से अधिक संपत्ति, शासन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इधर मामले में सीजे जॉयसन ने सभी आरोपों को नकारते हुए शिकायतों को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि मामले में विभाग द्वारा जांच की जा रही है। सीजे जॉयसन ने कहा कि जिस व्यक्ति द्वारा यह शिकायत की जा रही है, उसका संस्था से कोई लेना-देना नहीं है। झूठे आरोपों के साथ यह शिकायतें की गई हैं। सहायक संचालक, लोक शिक्षण सभाग भोपाल को जारी किए गए आदेश में लोक शिक्षण संचालक केके द्विवेदी ने कहा है कि इन शिकायती पत्रों का अवलोकन किया जाए।

आरजीपीवी में 10-11 मई को आयोजित होगा दो दिवसीय सृजन कार्यक्रम

इनोवेट एमपी मिशन के तहत सृजन के लिए पहुंचें 1568 प्रोजेक्ट

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में दो दिवसीय सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी), उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की सहभागिता से यह कार्यक्रम 10 एवं 11 मई 2025 को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. मोहन सेन के अनुसार प्रविष्टि की अंतिम तिथि 19 अप्रैल तक विश्वविद्यालय को प्रदेश की कुल 1568 प्रविष्टियां प्रोजेक्ट, मॉडल एवं पोस्टर के रूप में प्राप्त हो चुकी हैं जिसमें रूरल टेक्नोलॉजी में 214, क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी में 203, इंडस्ट्री 4.0/5.0 में 425, वेस्ट मैनेजमेंट में 125, लाइफ तथा हेल्थ साइंस में 280, एवं स्मार्ट एजुकेशन में 321 प्रविष्टियां शामिल हैं। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले दो दिवसीय सृजन कार्यक्रम में चयनित मॉडल एवं प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम के दौरान डिस्प्ले किया जाएगा। अगले चरण में 30 अप्रैल 2025 तक प्राप्त प्रविष्टियों में शीर्ष 150 प्रोजेक्ट्स का चयन कर उनकी अंतिम सूची जारी की जाएगी।



छात्र-छात्राओं से वर्किंग मॉडल और प्रोजेक्ट आमंत्रित किए थे

उल्लेखनीय है कि सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आरजीपीवी द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा उच्च शिक्षा विभाग से सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं से वर्किंग मॉडल और प्रोजेक्ट आमंत्रित किए थे। इसमें रूरल टेक्नोलॉजी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्री 4.0/5.0, वेस्ट मैनेजमेंट, लाइफ साइंस/स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्मार्ट एजुकेशन के रूप में 6 श्रेणियों में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दर्शाने वाले वर्किंग मॉडल, दृश्य आधारित या भौतिक प्रस्तुति आधारित डेमोस्ट्रेटिव मॉडल एवं प्रक्रियाओं या भविष्य की संभावनाओं को सिमुलेशन के माध्यम से प्रदर्शित करने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

आरजीपीवी :16 मई को होगा 12वां दीक्षांत समारोह, 150 विद्यार्थियों मिलेगी पीएचडी उपाधि

भोपाल, दोपहर मेट्रो। राजधानी स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह 16 मई को भोपाल स्थित रविन्द्र भवन के हंसखनी सभागार में संपन्न होगा। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगू भाई पटेल करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक, डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर जनरल पद्मश्री डॉ.वी.के.सारस्वत एवं विशिष्ट अतिथि मप्र शासन के तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं आयुष विभाग के मंत्री इन्दर सिंह परमार होंगे। 12वां दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर विभिन्न समितियों की बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजीव त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में विस्तृत कार्य योजना एवं उसके क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।

6 श्रेणियों में दिए जाएंगे कुल 36 पुरस्कार

सृजन के तहत निर्धारित 6 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में कुल 36 पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। सात्वता पुरस्कार के रूप में 12 पुरस्कार तथा महिला सशक्तिकरण के विशेष ज्यूरि पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। इनोवेट एमपी मिशन के तहत सृजन में चयनित प्रोजेक्ट्स को किसी भी प्रकार के बौद्धिक सम्पदा के पेटेंट फाइलिंग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता, उद्योग में काम करने के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण, शोधकर्ताओं के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, थिंकिंग जॉन, तथा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोटाइप के विकास हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

एक स्मार्ट पहल आजीवन खुशियों की गारंटी के लिए

एलआईसी का स्मार्ट पेंशन

☎ 512N382V01 स्थान संख्या: 879

एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, स्वतंत्र, वयस्क, तत्काल वार्षिकी योजना

ऑनलाइन भी उपलब्ध

- एकल प्रीमियम तत्काल वार्षिकी योजना
- आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिकी विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला
- एकल जीवन वार्षिकी और संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों में से चुनने की सुविधा
- प्रदेश के समय न्यूनतम आयु - 18 वर्ष

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

8976862090

अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए दल गठित करने का आदेश

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अक्षय तृतीया के अवसर पर पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13(4) एवं (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला व विकासखंड स्तर पर ग्राम, वार्ड और पंचायत स्तरीय समितियों व दलों का गठन करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि गठित समितियों

द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल गार्डन मलिक, खाना पकाने वाले रसोईया, कैटर्स, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मलिक के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस



शर्त पर जारी की जाएगी कि उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम ना हो। वर एवं वधू की सूची मय छायाचित्रों एवं आयु प्रमाण पत्र ना

होने की स्थिति में विवाह की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरु, बैंड वाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध

किया जाए की वर एवं वधू की उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत ही विवाह में सेवाएं प्रदान करें एवं सेवा प्रदाताओं की बैठक आयोजित की जाए।

सूचना तंत्र में शिक्षक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की सदस्य, शौचा दल अध्यक्ष, सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम वार्ड के सक्रिय नागरिक आदि हो सकते हैं। सूचना तंत्र ग्राम वार्ड में हो रहे विवाहों की जानकारी रखेंगे

तथा बाल विवाह होने पर कंट्रोल रूम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुभागीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल सूचित करेंगे।

जिला स्तर पर ब्लॉक परियोजना स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया जाए। कंट्रोल रूम में उपयोग में लाए जा रहे दूरभाष नंबर का प्रचार-प्रसार किया जाए कंट्रोल रूम में बाल विवाह की

सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित क्षेत्र के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचित किया जाए।

प्रचार-प्रसार

पुलिस थाना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नं. 181, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का दूरभाष नंबर, जिला एवं परियोजना स्तर पर गठित कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, दीवार लेखन व अन्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए।

कलेक्टर के आदेश का नगर पालिका और पुलिस 14 दिन बाद भी नहीं करा पाई पालन 27 अवैध कॉलोनाइजरों पर होनी है एफआईआर लेकिन, भूमि माफियाओं के आगे बेबस प्रशासन!

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

जनता जनार्दन के साथ धोखाधड़ी करने वालों अवैध कॉलोनी नाइजरों पर प्रकरण दर्ज करवाने के लिए कलेक्टर नगर पालिका सीएमओ को पत्र भेजा था जिसको 15 दिन गुजरने के बाद भी नगर पालिका इन पर मामला दर्ज नहीं करवा पाई है या फिर कहे इन्हें कलेक्टर के आदेश की इन्हें कोई चिंता नहीं है तभी तो आवेदन देख खाना पूर्ति कर दी आगे कार्रवाई हुई या नहीं उस पर ध्यान देना भी उचित नहीं समझा वही पुलिस ने भी दस्तावेजों का बहाना बनाकर मामला दर्ज नहीं किया या फिर भूमाफियाओं को बचाने में लगे हुए हैं। अवैध रूप से कॉलोनीकाटने वाले आम जनता के साथ सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। यह सब स्थानीय प्रशासन मिली भगत का नतीजा है कार्रवाई करने की जगह पर इनको उल्टा संरक्षण देने में लगी हुई जब कलेक्टर के आदेश पर ही नगर पालिका प्रशासन और पुलिस मामला दर्ज कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जैसे ही तत्कालीन कलेक्टर रोशनसिंह ने अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाली कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए थे। इनमें हड़कंप मच गया था उनके जाते ही भू माफिया फिर सक्रिय हो गए हैं। प्रकरण दर्ज करवाने वाला मामला भी ठंडा बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिनके कंधों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी कलेक्टर ने सौंपी है वहां आवेदन देकर भूल गए हैं। पुलिस इनके के आवेदन पर क्या



आगे कार्रवाई की या नहीं उसकी जानकारी जुटाना भी है इन्होंने जरूरी नहीं समझा रहा है। अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों पर मामला दर्ज नहीं करवाया चाहते हैं तभी तो बिना दस्तावेजों के कलेक्टर का पत्र लगाकर नगर पालिका के अधिकारी भूल गए पुलिस के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका को पत्राचार किया है उसका भी नगर पालिका से कोई जवाब पुलिस के पास नहीं पहुंचा है इस वजह से पुलिस आगे कार्रवाई करने में अपने आप को असमर्थ बता रही है। यदि पुलिस प्रशासन चाहे तो सूची के हिसाब से कार्रवाई कर सकती है लेकिन यह भी नहीं कर रहे हैं। इसका फायदा अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले उठा लूट मरी करने में लगे हुए हैं।

कलेक्टर के बदलते ही अधिकारी हुए ठंडे

लंबी मेहनत करने बाद कलेक्टर रोशन

सिंह अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई की पूरी तैयारी कर गए उसको आगे बढ़ाने जिम्मेदारी तत्कालीन कलेक्टर अंशुल गुप्ता की है। लेकिन यह इस मामले में रुचि दिखाएंगे या नहीं यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा अभी तो अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले जरूर खुश नजर आ रहे हैं अवैध कॉलोनी वालों की फाइल पूरी तरह से रुक गई है।

इन पर एफआईआर हो जाती पर कलेक्टर बदलते ही मामला ठंडा बस्ते डाल दिया गया है नगर पालिका परिषद के अधिकारी और पुलिस भी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है वहीं देखना है कि कलेक्टर जनता को न्याय दिलाने के लिए अवैध रूप से कॉलोनी काटकर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले पर प्रकरण दर्ज करवा पाएंगे या फिर मामले को दफा रफा हो जाएगा और भू माफिया कि तरह बल्ले बल्ले होती रहेंगी।

भूमाफियाओं के आगे बेबस प्रशासन

जनता के साथ खुलेआम गोलमाल करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की जगह पर प्रशासन के अधिकांश अधिकारी उनको संरक्षण देने में लगे हुए इसी वजह से अवैध कॉलोनी की संख्या डेढ़ सौ के करीब पहुंच गई है। यह स्थानीय अधिकारियों को गंभीरता से ही नहीं लेते हैं। वह शिकायतों को भी स्थानीय अधिकारी कर भाई के नाम पर औपचारिकता पूरी करते हैं। आम आदमी की आवाज को हमारे संवाददाता प्रमुखता से प्रकाशित किया खबर के बाद तत्कालीन कलेक्टर रोशन सिंह ने अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों पर शिकंजा करते हुए एफआईआर करवाने की फाइल को आगे बढ़ाया दिया था। उनके जाते ही मामला शांत हो गया है। दोपहर मेट्रो आम जनता की आवाज इसी तरह बुलंद करता रहेगा।

इनका कहना है

बिना दस्तावेज के आवेदन पत्र नगर पालिका ने दिया है हमने दस्तावेज के लिए नगर पालिका को लिखा है जैसे ही दस्तावेज मिलेंगे हम कार्रवाई करेंगे।

—उमेश कुमार तिवारी एसडीओपी इस मामले को मैं देखवाता हूँ आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है हम करवाएंगे।

—अंशुल गुप्ता कलेक्टर

थाना लटेरी के अपराधी पर नगद इनाम की घोषणा

सिरोंज। विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानि ने थाना लटेरी जिला विदिशा में दर्ज अपराध के फरार आरोपियों की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी कराने में मदद करने वाले के लिए दो-दो हजार रूपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। थाना लटेरी में दर्ज अपराध प्रकरण क्रमांक 10/2025 के फरार आरोपी सोनू पुत्र मांगीलाल गुर्जर उम्र 32 साल, जसवंत पुत्र आशाराम गुर्जर उम्र 41 साल, आशाराम पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 75 साल, मांगीलाल पुत्र ओमकार गुर्जर उम्र 58 साल, विक्रम पुत्र आशाराम गुर्जर उम्र 48 निवासीगण दलपागंडा थाना लटेरी की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए दो-दो हजार रूपए (प्रत्येक पर) नगद इनाम घोषित किया गया है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

एसडीएम के निर्देश पर एचडीएफसी बैंक के आगे से हटा ट्रांसफार्मर

ट्रांसफार्मर से कई बार हो चुकी हैं दुर्घटनाएं

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

विगत महीने पहले विधायक उमाकांत शर्मा ने मंडी बाईपास रोड का जायजा लिया था उस समय एचडीएफसी बैंक सामने नाले में रखे बिजली ट्रांसफार्मर को यह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए उन्होंने एसडीएम हर्षल चौधरी को निर्देश दिए थे। इसके बाद एसडीएम ने बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को ट्रांसफर यहां से बदलवाने के लिए पत्र लिखा पर काफी प्रयासों बाद एचडीएफसी बैंक सामने से बिजली वितरण



कंपनी ने गुरुवार को बिजली ट्रांसफार्मर को यहां से हटकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया यहां पर ट्रांसफार्मर होने के कारण कई बार

दुर्घटनाएं भी हो चुकी थी बड़ी घटना को ट्रांसफार्मर दावत दे रहा था नाले का निर्माण भी इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था।

एसडीएम के निरीक्षण में खुली थी पोल

फटकार के बाद राजीव गांधी जन चिकित्सालय प्रबंधन ने फटे हुए गद्दों को बदलवाया

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय का सोमवार को एसडीएम हर्षल चौधरी ने औचक निरीक्षण किया था उनके समने अस्पताल के वाडों में फटे हुए गद्दे और चादर गायब उसके बाद एसडीएम ने जिम्मेदारों को फटकार लगाते व्यवस्था तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए थे एसडीएम ने बीएमओ विकास सिंह बघेल को फटे हुए गद्दे बदलवाने और इन पर चादर की व्यवस्था नहीं होने पर नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण के साथ नए गद्दे चादर की व्यवस्था करने का अल्टीमेटम दिया था उसका परिणाम आ गया बीएमओ ने



फटे हुए गद्दे को बदलवा दिया चादर डाले हुए थे इससे पहले इनका कोई आता पता नहीं था फटे हुए गद्दे से ही काम चलाया जा रहा था मरीजों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना हुआ था अस्पताल के जिम्मेदारों इनकी कोई चिंता नहीं थी साफ

सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को भी ठीक करने के निर्देश दिए थे। हमारे संवाददाता एसडीएम की जांच में मिली लापरवाहियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था इसके बाद अस्पताल के अंदर की तस्वीर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

कायरतापूर्ण हमला कर निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतारा पहलगाम आतंकी हमले में मृत आत्माओं को थोक अनाज तिलहन संघ ने दी श्रद्धांजलि

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

गुरुवार को थोक अनाज तिलहन व्यापार संघ ने पहलगाम हमले के विरोध में मंडी में नीलामी 15 मिनट देर से प्रारंभ की, पहलगाम में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण हमला कर निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतारा दिया और अनेक को घायल कर दिया, पूरे देश में शोक की लहर है, हम व्यापारी भी बहुत दुःखी और रोष में हैं। व्यापारियों ने दो मिनट का मौन रखकर हमले में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से माँग की इस घटना में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे को ऐसी घटना



की कभी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो पाए। इस दौरान व्यापारी समीर भार्गव, राजेश जैन, गगन तारण, मोंटू जैन टिंगू साहू, शैलू जैन, रामू राठौड़

, उमेश गोयल, लवी साहू, गोपेश भार्गव, नेतराम रघुवंशी, मिथिलेश महाराज सहित में मंडी के कर्मचारी व किसान मौजूद थे।

कलेक्टर ने किया कार्यालयों का औचक निरीक्षण

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने गुरुवार को पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित सभी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने किसी को भी बिना सूचना दिए सवा दस बजे कार्यालयों में पहुंचकर अधिकारी, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया। मौके पर अनुपस्थितों की हाजिरी कॉलम में क्रास का चिन्ह मार्क करते हुए अनुपस्थितों की सूची संधारित कर उन्हें शोर्काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने पुरानी कलेक्ट्रेट में संचालित जिला शिक्षा केन्द्र, शहरी विकास



अभिकरण, उद्यानिकी, मत्स्य, ओबीसी कार्यालय के अलावा भण्डार कक्षों में पहुंचकर निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए वहीं संधारित विभिन्न प्रकार की पंजियों की जानकारी प्राप्त की वहीं विभागीय हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रदर्शन हेतु दीवारों पर जानकारी अंकित कराने के निर्देश दिए हैं।



कलेक्टर से चयनित होने के उपरांत प्रशांत ने सौजन्य भेंट की

सिरोंज। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता से गुरुवार को यूपीएससी में चयनित प्रशांत धाकड़ ने चैम्बर में पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की। कलेक्टर श्री गुप्ता ने श्री धाकड़ को बुके देकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। गौरतलब हो कि विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील के ग्राम पाली निवासी प्रशांत धाकड़ ने पहली ही कोशिश में यूपीएससी परीक्षा पास की और 596वीं रैंक हासिल की है।

